

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2012/अग्रहायण 23, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216

No. 202]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2012/AGRAHAYANA 23, 1934

[N.C.T.D. No. 216

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2012

फा. सं. 529/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 के अधिनियम 26) की धारा 7, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद्वारा उच्च न्यायालय नियम, तथा आदेश, खंड-V, अध्याय 6-L में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

वर्तमान अध्याय 6-L को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

भाग L

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किये जाने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विरचित किये गए नियम

यह नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. एक अधिवक्ता को या तो (i) स्व प्रेरणा से, अथवा (ii) इसमें, इन नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किए जाने हेतु विचारित किया जा सकेगा।

2. पात्रता शर्तें :

कोई व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत नहीं किया जाएगा जब तक कि—

- वह न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि तक विधि व्यवसाय न कर चुका हो;
- वह दिल्ली विधिज्ञ परिषद् में नामांकित न हो;

- (iii) वह मुख्यतः दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्ययसाय न कर रहा हो;
- (iv) वह पिछले तीन वर्षों में ऐसे कम से कम पन्द्रह निर्णयों में शामिल न रहा हो जिससे विधि विकास में योगदान हुआ हो।

स्पष्टीकरण :-

एक व्यायसायिक अधिवक्ता के रूप में कम से कम अनुभव के सम्बन्ध में योग्यता शर्तें, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों या जिन्होंने 10 वर्षों के अनुभव तथा/या सेवा के पश्चात् पद त्याग किया हो, तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए लागू नहीं होंगी।

3. एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मनोनयन के लिए नामित व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की सिफारिश उसे इस प्रकार मनोनीत होने से अयोग्य कर देगी।
4. किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में स्व प्रेरणा से मनोनयन के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

उस अधिवक्ता को जो पूर्व विहित शर्तों को पूरी करता हो, न्यायालय द्वारा स्व प्रेरणा से एक न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत करने हेतु प्रस्तावित करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव पर माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों की दो-तिहाई संख्या से अनौपचारिक रूप से मंत्रणा करेंगे। यदि यह प्रस्ताव

मंजूर हो जाता है तथा सम्बंधित अधिवक्ता अपनी सहमति देता है तो इस विषय को वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पास करने हेतु पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा ।

5. स्व प्रेरणा से मनोनीत करने के अलावा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत करने की प्रक्रिया ।

- (i) किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव, जो उपरोक्त योग्यता शर्तें पूरी करता हो, उसकी वैयक्तिक सूचना एवं स्वीकृति पत्रक (इसके उपाबंध 'ए') सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा पूर्ण रूप से लिखित एवं हस्ताक्षरित घोषणा सहित, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनोनीत संयुक्त रूप से पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं, जिनकी वैयक्तिक वकालत न्यायालय में 5 वर्षों से कम न हो द्वारा, प्रस्तुत किया जाएगा एवं महानिबंधक को अग्रेषित किया जाएगा ।
- बशर्त कि ऐसे कोई वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्ण न्यायालय द्वारा किये गए दो निरंतर विचारों में दो से अधिक नामों का प्रस्ताव नहीं देंगे ।

- (ii) किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत करने के ऐसे प्रस्ताव को महानिबंधक द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख, पूर्ण न्यायालय के सामने विचारार्थ तथा गुप्त मत द्वारा मतदान हेतु रखे जाने के निर्देश प्राप्त करने के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा । प्रस्ताव को पूर्ण न्यायालय अधिवेशन से एक सप्ताह पूर्व न्यायाधीशगण के समक्ष प्रस्ताव परिचालित किया जायेगा । यदि प्रस्ताव दिए गए

कुल मतों की दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित हो जाता है, तो पूर्ण न्यायालय अधिवेशन में मत देने वाले न्यायाधीश के उपस्थित अथवा अनुपस्थित होने को विचार किये बिना, जहाँ पदासीन न्यायाधीशगण के कुल सदस्य-संख्या की दो-तिहाई ने मत दिया हो, सम्बंधित अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत हो जायेगा। न्यायाधीशों की दो-तिहाई संख्या की गणना करते समय, न दिए गए अथवा खाली छोड़े गए मत नहीं गिने जायेंगे एवं अपूर्णाक को नजरअंदाज किया जाएगा और केवल पूर्ण संख्या की ही गणना की जाएगी।

6. वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत किये जाने के प्रत्येक प्रस्ताव में यह प्रमाणित किया जाएगा कि सम्बंधित अधिवक्ता को प्रस्ताव की तिथि से पूर्व एक वर्ष के अन्दर दिल्ली उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे पद हेतु विचारित नहीं किया गया।
7. यदि कोई प्रस्ताव पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुकूल रूप से विचारित नहीं किया जाता है, तो सम्बंधित अधिवक्ता ऐसे विनिश्चय होने की तिथि से एक वर्ष तक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मनोनीत होने के लिए अनुशंसा के योग्य नहीं होगा और इसकी सूचना सम्बंधित अधिवक्ता तथा प्रस्तावकों को दी जायेगी।
8. उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो दिल्ली बार काउन्सिल में अपना नामांकन कराने पर दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिये अधिकृत है, यदि

वह मुख्य न्यायाधीश को अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत होने की इच्छा से अवगत कराता है, तो उसे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

9. पूर्ण न्यायालय से अपने विनिश्चय के लिये कारण बताना अपेक्षित नहीं है।

उपाबंध 'ए'

सहमति और बायो डाटा का प्रारूप

1. नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. पता :
4. जन्मतिथि :
5. अर्हताएं :
6. अधिवक्ता के तौर पर नामांकन की संख्या एवं तिथि तथा नामांकन का स्थान :
7. तिथि जब से विधि व्यवसाय में निरंतर कार्यरत हैं तथा कार्य का स्थान :
8. सेवा की अवधि और वकालत का अनुभव, यदि राज्य न्यायिक सेवा के पूर्व सदस्य हैं :
9. विधि की विभिन्न शाखाएं जिनमें विशिष्ट अनुभव हो :
10. क्या दिल्ली उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

पहले कभी और प्रस्ताव/सहमति की तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर आपको
4624 DG/12-2

वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर अभिहित करने हेतु विचार किया गया ? (यदि किसी न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लंबित हो तो उसके बारे में भी बताएं) :

11. कोई अन्य सूचना जो विद्वान अधिवक्ता देना चाहें :

नोट : उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिये यदि इस प्रारूप में दिया गया स्थान अपर्याप्त लगे तो अलग पृष्ठ का भी प्रयोग किया जा सकता है ।

सहमति

मैं _____ अधिवक्ता, एतद्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2)

की शर्तों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता अभिहित होने हेतु अपनी सहमति देता हूँ तथा तत्समय प्रवृत्त या इसके पश्चात् इस हेतु विहित किये जाने वाली समस्त विधियों, नियमों, विनियमों, मानदंडों एवं दिशानिर्देशों, का पालन करने का वचन एवं सहमति देता हूँ ।

स्थान :

तिथि :

हस्ताक्षर

न्यायालय के आदेशानुसार,

वी. पी. वैश्य, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 14th December, 2012

F. No. 529/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 6-L, Volume V of High Court Rules and Orders :—

The following shall be substituted for the existing Chapter 6-L :-

Part L

**RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF DELHI UNDER SECTION 16(2)
OF THE ADVOCATES ACT, 1961 FOR DESIGNATING AN ADVOCATE AS
SENIOR ADVOCATE**

These Rules shall be effective from the date of publication in the Delhi Gazette.

1. An advocate may be considered for being designated as a Senior Advocate either
(i) suo motu; or (ii) in accordance with the procedure prescribed herein in these Rules.
2. **ELIGIBILITY CONDITIONS:**

No person shall be designated as a Senior Advocate unless he-

- (i) has practiced as an Advocate at the Bar for not less than 10 years;
- (ii) is enrolled with the Bar Council of Delhi;
- (iii) has been mainly practising in the High Court of Delhi and the Courts Subordinate to it;
- (iv) has furnished at least fifteen judgments, in the preceding three years, where he has contributed to the growth of law.

EXPLANATION:

The eligibility condition with regard to minimum standing as a practising Advocate shall not apply to retired Judicial Officers or those who have resigned having service and/or practice of 10 years at their credit and retired High Court Judges.

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 14th December, 2012

F. No. 529/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966), Section 16(2) of the Advocates Act, 1961 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 6-L, Volume V of High Court Rules and Orders :—

The following shall be substituted for the existing Chapter 6-L :-

Part L

**RULES FRAMED BY THE HIGH COURT OF DELHI UNDER SECTION 16(2)
OF THE ADVOCATES ACT, 1961 FOR DESIGNATING AN ADVOCATE AS
SENIOR ADVOCATE**

These Rules shall be effective from the date of publication in the Delhi Gazette.

1. An advocate may be considered for being designated as a Senior Advocate either (i) suo motu; or (ii) in accordance with the procedure prescribed herein in these Rules.

2. **ELIGIBILITY CONDITIONS:**

No person shall be designated as a Senior Advocate unless he-

- (i) has practiced as an Advocate at the Bar for not less than 10 years;
- (ii) is enrolled with the Bar Council of Delhi;
- (iii) has been mainly practising in the High Court of Delhi and the Courts Subordinate to it;
- (iv) has furnished at least fifteen judgments, in the preceding three years, where he has contributed to the growth of law.

EXPLANATION:

The eligibility condition with regard to minimum standing as a practising Advocate shall not apply to retired Judicial Officers or those who have resigned having service and/or practice of 10 years at their credit and retired High Court Judges.

3. Canvassing by a nominee for designation as a Senior Advocate shall disqualify him for being so designated.

4. **PROCEDURE TO BE FOLLOWED WITH REGARD TO SUO MOTO DESIGNATION OF AN ADVOCATE AS SENIOR ADVOCATE.**

An Advocate who fulfills the conditions prescribed hereinbefore, may be considered *suo moto* by the Court for being designated as a Senior Advocate either on the proposal of a Judge or of the Chief Justice. Upon such proposal, the Chief Justice shall informally confer with two-third strength of the Judges. In case the proposal finds approval, and the Advocate concerned gives his consent it shall be placed before the Full Court for passing of a formal resolution, designating him as Senior Advocate.

5. **PROCEDURE FOR DESIGNATION OF AN ADVOCATE AS SENIOR ADVOCATE OTHER THAN SUO MOTO DESIGNATION.**

- (i) The proposal for designation of an Advocate as Senior Advocate, who fulfills the eligibility conditions mentioned above, shall be initiated and forwarded to the Registrar General, jointly by five Senior Advocates designated by Delhi High Court, with not less than five years individual standing at the Bar as such, accompanied by a personal information-cum-consent sheet (Annexure 'A' hereto) duly filled in and signed by the Advocate concerned.

Provided that no such Senior Advocate shall propose more than two names in two consecutive considerations by the Full Court.

- (ii) The proposal for designation of an Advocate as Senior Advocate so made will be submitted by the Registrar General to the Chief Justice, seeking directions for placing it before the Full Court for consideration and voting by secret ballot. The proposal shall be circulated amongst the Judges one week before the Full Court meeting. If the proposal is approved by a two-third majority of the total ballot cast, irrespective of the Judge casting ballot being present or not in the Full Court meeting, where at least two-third of the total strength of the sitting Judges have cast their ballot, the Advocate concerned shall stand designated as Senior Advocate. While calculating two-third number of the Judges, ballot not cast or left blank shall not be counted and fraction shall be ignored and only whole number shall be taken into account.
6. Every proposal initiated for designation as Senior Advocate shall certify that the concerned Advocate had not been considered for such designation by the Delhi High Court or any other High Court or the Supreme Court within one year prior to the date of proposal.
 7. If a proposal is not favourably considered by the Full Court, the concerned Advocate would not be eligible for being recommended for designation as a

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2012

फा. सं. एफ 6(168)/आईटी/टेक/2012/6034.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6 एवं 6क के साथ पठित धारा 90 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता) नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा।
 - (2) यह सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।
 - (3) यह नियमावली दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगी।
2. **परिभाषाएं** :— (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में:—
 - (क) “अधिनियम” का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से है;
 - (ख) “प्राधिकृत एजेंट” का अर्थ किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता का कोई एजेंट और इसमें किसी इलेक्ट्रॉनिकली समर्थ क्योस्क/खोखे का कोई ऑपरेटर या कार्यालय सहित जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करके किसी कम्प्यूटर साधन या किसी अन्य सम्प्रेषण यंत्र की सहायता से प्रयोक्ताओं को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान के लिये अनुमत्त किया गया है;
 - (ग) “प्राधिकृत सेवा प्रदाता” का अर्थ किसी अभिकरण से है, जिसमें इन नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली सेवा प्रदान करने की किसी प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन के लिये निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई निगमित निकाय या अभिकरण शामिल है।

- (घ) "निगमित निकाय" का अर्थ कोई कंपनी और इसमें कोई फर्म आती है जो वाणिज्यिक या व्यवसायिक गतिविधियों में पूर्णतः स्वामित्व हों या व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन हो;
- (ङ) "प्रमाण पत्र" का अर्थ किसी व्यक्ति का पद, अधिकार या दायित्व, सरकार के किसी ऐसे अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अनुसार, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, की पुष्टि करने के लिये सरकार संबद्ध अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अन्तर्गत सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के लिये अपेक्षित किसी प्रमाण पत्र से है और इसमें निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता द्वारा यथा निर्धारित ऐसी लेखन सामग्री पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से सक्षम प्राधिकरण/प्राधिकारी या किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फार्म में मुद्रित करके सौंपा गया कोई प्रमाण पत्र भी शामिल है;
- (च) "सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण" का अर्थ सरकार के सचिव, सरकार के प्रत्येक विभाग का प्रधान और सरकारी संगठनों तथा निकायों के प्रधान, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;
- (छ) "निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान" का अर्थ निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान के रूप में अधिसूचित सरकार कर्मचारी से है;
- (ज) "ई-सेवा" का अर्थ अधिसूचना द्वारा यथविनिर्दिष्ट और प्रयोक्ता को इलेक्ट्रॉनिकली रूप से प्रदान की गई किसी सेवा से है;
- (झ) "इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान" का अर्थ प्रपत्रों और आवेदन पत्रों की पावती के रूप में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, किसी प्रकार के लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन की उपलब्धता तथा इन नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करके इलेक्ट्रॉनिक साधनों से धनराशि की प्राप्ति तथा भुगतान या प्रदान की गई किसी अन्य ऐसी सार्वजनिक सेवा से है;
- (ञ) "सरकार" का अर्थ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;
- (ट) "अधिसूचना" का अर्थ शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना से है;
- (ठ) "शासकीय राजपत्र" का अर्थ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासकीय राजपत्र से है;
- (ड) "सार्वजनिक सेवा" का अर्थ चाहे सरकार के किन्हीं सक्षम प्राधिकारियों या इसके किन्हीं अभिकरणों से, चाहे सीधे या किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा से है, जिसमें इसके साथ-साथ शामिल होंगे, पावती या प्रपत्र तथा आवेदन पत्र, किसी लाइसेंस परमिट, प्रमाण पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन की प्राप्ति तथा धनराशि की प्राप्ति या भुगतान;
- (ढ) "सेवा प्रभार" का अर्थ सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदान करने के लिये प्राधिकृत सेवा प्रदाता को सरकार द्वारा देय यथाविनिर्दिष्ट राशि से है और इसमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा देय किसी सेवा के संबंध में देय कोई विधिवत् प्राधिकृत कर प्रभार, देयताएं कोई अन्य धनराशि नहीं आती है, जो संबंधित प्राधिकारी को कोई आवेदन करते समय सरकार के संबंध अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अन्तर्गत अन्यथा देय है;

- (ण) "हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी" का अर्थ किसी प्रकार का लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन जारी करने के लिये सरकार के सम्बद्ध अधिनियम, नियमावली, विनियमावली या आदेश के अन्तर्गत सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
- (त) "विनिर्दिष्ट" का अर्थ सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट से है;
- (थ) "राजकीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भंडार" का अर्थ डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिकली हस्ताक्षरित सभी प्रकार के किसी इलेक्ट्रॉनिक भंडार से है, ऐसे अभिलेख की उपलब्धता के प्रयोजन तथा नागरिकों को उनकी सुपुर्दगी के लिये प्राधिकारी द्वारा जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखरखाव किया गया हो।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा न परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन अधिनियम में परिभाषित, का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. **इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्राप्ति प्रणाली :-** (1) कुशल सेवा उपलब्ध के प्रयोजनार्थ सरकार इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्राप्ति के लिये इलेक्ट्रॉनिकली समर्थ क्योस्क या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं देने के लिये किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता को प्राधिकृत कर सकती है।

व्याख्या:- इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान नियम प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं और प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से ई-सर्विस प्राप्ति के संचालन के लिये व्यवस्था करते हैं, जबकि ई-सर्विस प्रदान करने के अन्य तंत्र जैसे राज्य ऑन लाइन पोर्टल, सरकार के विभागीय विक्रय केन्द्र और वेब पर सीधे ही ऑन लाइन सेवाएं प्रयोक्ताओं से उपलब्ध कराई गईं। सम्बद्ध सरकारी विभागों तथा अभिकरणों द्वारा सामान्य पद्धति से संचालित होंगी।

- (2) किसी प्रकार की ई-सर्विस के संबंध में इन नियमों के अन्तर्गत जारी आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र का प्रपत्र सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगा।

4. **इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की सूची अधिसूचित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का दायित्व :-** (1) प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के प्रवृत्त होने से तीस दिन की अवधि के भीतर अधिसूचित करेगा।

- (क) उस विभाग, अभिकरण या निकाय की सार्वजनिक सेवाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

- (ख) जिस तिथि से प्रत्येक ऐसी सेवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ग) सेवा स्तर के रूप में कार्यकुशलता गुणवत्ता और शुद्धता के मानक निर्धारित करना, और
- (घ) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसी प्रत्येक सेवा प्रदान करने हेतु पदनामित अधिकारीगण।
2. तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी इन प्रकाशनों पर प्रति वर्ष या जब बार-बार आवश्यक हो, समीक्षा तथा अद्यतन करेंगे।
5. **हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की अधिसूचना:—**(1) सक्षम प्राधिकारी, विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं और उनकी राज्य में सम्बद्ध क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं, ऐसी सेवा की प्रकृति, हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी, प्राधिकारी के कार्यकाल की अवधि और ऐसी प्रत्येक प्राधिकरण के क्षेत्र के विधिवत् विस्तार के संबंध में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की सूची अधिसूचित करेंगे।
- (2) सक्षम प्राधिकारी हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों के पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन या सेवा समाप्ति संबंधी तत्काल निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को सूचित करेंगे।
- (3) हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन तथा सेवा समाप्ति के संबंध में उनके सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी को इनके संबंधित एप्लीकेशन साफ्टवेयर के खंड (2) क्रियान्वयन में परिवर्तन का उल्लेख करना चाहिए।
6. **इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक के कार्य एवं शक्तियां :—** (1) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक मुख्यतः निम्न कार्य एवं शक्तियों का निष्पादन करेंगे :—
- (क) प्राधिकृत सेवा प्रदाता की सेवा को प्राधिकृत, निलंबित या समाप्त करना;
- (ख) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत एजेंट्स द्वारा प्राधिकृत एजेंट्स के चयन के संबंध में प्रतिमानक का निर्धारण;
- (ग) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत एजेंट्स के कार्य, उत्तरदायित्व तथा दायित्व का निर्धारण;
- (घ) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत एजेंट्स द्वारा सेवा स्तरों पर लागू प्रतिमानक का निर्धारण;
- (ङ) ई-सर्विस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत एजेंटों द्वारा वसूले जाने वाले सेवा प्रभार का निर्धारण;

4624 DG/12-4

- (च) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत एजेंटों के सेवा के प्राधिकरण, निलंबन या समापन से संबंधित निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण;
- (छ) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत एजेंटों की सेवा के निलंबन या समापन के मामले में, ई-सर्विस की डिलीवरी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- (2) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक अपनी कोई भी शक्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय को प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सौंप सकता है।
7. **इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के लिए प्राधिकृत सेवा प्रदाता :-** प्राधिकृत सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी के निदेशक द्वारा निर्धारित उचित डिलीवरी अवसंरचना तथा नेटवर्क या प्राधिकृत एजेंट द्वारा उपभोक्ताओं को इन नियमों के अनुरूप अधिसूचित जन सेवा इलेक्ट्रॉनिकली प्रदान करेंगे।
8. **प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकृत एजेंट्स की नियुक्ति:-** (1) प्राधिकृत सेवा प्रदाता इतने प्राधिकृत एजेंट नियुक्त करेंगे ताकि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित दक्षता, गुणवत्ता तथा यथार्थता के प्रतिमानक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली सेवा प्रदान की जा सके।
- (2) प्राधिकृत सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे तथा प्राधिकृत एजेंट पब्लिक सेवा इलेक्ट्रॉनिकली प्रदान करने के लिए प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
- (3) प्राधिकृत सेवा प्रदाता प्राधिकृत एजेंट को उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे ताकि वे दोष रहित तरीके से तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान कर सकें।
9. **प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रचालन प्रारंभ करना :-** प्राधिकृत सेवा प्रदाता केवल निम्न पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी का वाणिज्य प्रचालन प्रारंभ करेंगे :-
- (क) इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपनाई प्रक्रिया और मानदंड के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी के निदेशक के डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ई-मेल के माध्यम से या लिखित में पुष्टि करेंगे; तथा
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक द्वारा निर्धारित प्रतिमानक के निबंधन में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी तथा दोष रहित तरीके के लिए सुविधा एवं अवसंरचना स्थापित करना

तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी के निदेशक के डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा लिखित या ई-मेल के माध्यम से इसकी पुष्टि करना।

10. **प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा सर्विस प्रभार वसूलना:-** (1) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट को उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई-सर्विस के लिए आवेदन करते समय इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार भी देने होंगे जोकि आवेदन करते समय प्राधिकृत सेवा प्रदाता को नकद में देय होंगे।
- (2) ई-सर्विस की अधिसूचना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी के निदेशक सेवा प्रभार का निर्धारण करेंगे।
- (3) भिन्न-भिन्न ई-सर्विस के लिए सेवा प्रभार अलग-अलग होंगे जैसे:-
- (क) स्थिति पूछताछ;
- (ख) ई-सर्विस से संबंधित प्रिंट आउट;
- (ग) ई-सर्विस से संबंधित दस्तावेजों की स्कैनिंग;
- (घ) पावती रसीद; तथा
- (ङ) कोई अन्य ई-सर्विस।
- (4) सेवा प्रभार में कोई प्राधिकृत कर, प्रभार, देय या संबंधित सक्षम प्राधिकार के किसी व्यक्ति द्वारा देय सेवा के संबंध में कोई अन्य राशि शामिल नहीं होगी जोकि संबंधित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करते समय सरकार के अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अंतर्गत अन्यथा देय होंगे।
11. **सेवा प्रदाता द्वारा वसूल किये जाने वाला शुल्क :-** (1) संबंधित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करते समय सरकार के संबंधित नियम, अधिनियम, विनियम या आदेश के अन्तर्गत संबंधित सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा देय सर्विस के संबंध में शुल्क या विधिवत् प्राधिकृत कर, प्रभार, देय या अन्य कोई देय राशि के संबंध में वसूली मामले के अनुसार प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट द्वारा की जाएगी, कोर्ट फीस स्टॉप या खजाना चलान के रूप में दिए जाने वाले भुगतान को छोड़कर।

- (2) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट द्वारा एकत्र की गई फीस सरकारी खजाने में जमा कराई जाए जैसाकि मामले के अनुसार प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक द्वारा निर्धारित किया गया है।
12. सेवा प्रदाता द्वारा भेजी गई राशि या सेवा प्रभार तथा शुल्क :- (1) ई-सर्विस के लिए प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत या प्राधिकृत एजेंट द्वारा एकत्र सेवा प्रभार में से इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा प्रभार का प्रतिशत सरकार को दिया जाएगा।
- (2) इस प्रकार एकत्र किया गया सेवा प्रभार में से सरकार का हिस्सा प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट द्वारा सरकारी खजाने में भेजा जाएगा जैसाकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक द्वारा निर्धारित है।
13. सेवा प्रदाता को देय संभावित सेवा प्रभार तथा ई-सर्विस प्राप्त करने की अन्य शर्तों के संबंध में :- (1) जहां कोई व्यक्ति किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट को अधिसूचित ई-सर्विस के संबंध में सेवा प्रभार देता है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के निदेशक द्वारा निर्धारित प्रिंट आउट या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान रसीद में उचित तरीके से पावती देंगे तथा प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे वो सामान्यतः भुगतान के साक्ष्य के रूप में रखेगा और यह माना जाएगा कि सामान्य परिस्थितियों में संभावित पावती देय या दावा की संतुष्टि करेंगे।
- (2) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट को भुगतान किए गए सेवा प्रभार से संबंधित व्यक्ति को अधिसूचित ई-सर्विस प्राप्त करने का कोई अधिकार या शीर्ष, स्थायी या अस्थायी अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- (3) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत एजेंट को भुगतान करते समय सर्विस की डिलीवरी के साथ संबंधित शर्तों में सर्विस की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भुगतान।
14. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी की प्रणाली अपनाने के लिए सरकार के द्वारा या पक्ष में राशि का भुगतान या पावती :- इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी की प्रक्रिया अपनाने के लिए सरकार के पक्ष में या सरकार द्वारा राशि की प्राप्ति या भुगतान को सरकार के वित्तीय कोड या खजाना कोड के साथ अनुपालन में प्राप्ति या भुगतान को प्रभावी माना जाए।

15. **फार्म, आवेदन या अन्य दस्तावेज भरना :-** (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित कोई फार्म, आवेदन या अन्य दस्तावेज किसी कार्यालय, अधिकरण, निकाय, एजेंसी या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा उसके लिये विनिर्दिष्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग करके भरा जा सकता है।
- (2) उप खंड (1) में उल्लिखित कार्यालय, अधिकरण, एजेंसी या अधिकृत सेवा प्रदाता ऐसा साफ्टवेयर विकसित करते समय इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, अर्थात् :-
- (क) जीवन अवधि;
 - (ख) संरक्षणता;
 - (ग) प्रवेश सुगमता;
 - (घ) पठनीयता;
 - (ङ) संबंधित सूचना के विषय में व्यापकता;
 - (च) प्रामाणिकता एवं सत्यता की दृष्टि से साक्ष्य महत्व;
 - (छ) नियंत्रित विनष्टशीलता; तथा
 - (ज) वर्धनशीलता।
16. **लाइसेंस, परमिट, संस्वीकृति या अनुमोदन जारी करना :-** (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित किसी लाइसेंस, परमिट, संस्वीकृति या अनुमोदन को जारी या प्रदान करने के लिए नियम 15 में विनिर्दिष्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है।
- (2) इस विधि से जारी किये जाने वाले लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदन का स्वरूप संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश में उल्लेख के अनुसार होगा तथा उस पर डिजिटल हस्ताक्षर तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम लिखा होगा तथा रिकार्ड तैयार करने की तिथि तथा समय दिया होगा।
17. **डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का भंडार निर्माण :-** (1) सक्षम प्राधिकारी इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद यथासंभव शीघ्र डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का डाटाबेस तैयार

4624 D5/12-5

करेगा तथा भंडारण का सृजन, स्थापना तथा अनुरक्षण करेगा जिसमें साथ ही एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा वर्क फ्लो का उल्लेख होगा ताकि अधिकृत सेवा प्रदाता या अधिकृत एजेंट इन लाइसेंसों, परमिटों, प्रमाण पत्रों, स्वीकृति या अनुमोदन, जैसी भी स्थिति हो, तक प्रवेश करके प्रयोक्ता को प्रदान कर सके।

- (2) सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, सूचना, एप्लीकेशन, डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों के विषय में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संबंधित सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे।

18. डिजिटल हस्ताक्षर वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों के भंडारण में परिवर्तन करने की प्रक्रिया :— (1) कोई सक्षम प्राधिकारी या हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी स्वतः या संबंधित पक्ष के आवेदन पर संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के भंडारण में समुचित परिवर्तन कर सकते हैं।

- (2) ऐसे प्राधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों में परिवर्तन करने या आदेश देने का विशेषाधिकार होगा।

- (3) डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के भंडारण में किसी रिकार्ड में किसी बढ़ोतरी या घटाने संबंधी परिवर्तन पर संबंधित प्राधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करेगा तथा समस्त परिवर्तनों की इलेक्ट्रॉनिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया अनुरक्षित की जायेगी।

19. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान हेतु विशेष एप्लीकेशन साफ्टवेयर का निर्माण :— सक्षम प्राधिकारी ऐसे एप्लीकेशन साफ्टवेयर का निर्माण करवाएगा जिसका प्रयोग करके हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी लाइसेंसों, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदनों को डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और तीसरे पक्ष एजेंसी से इसकी लेखा परीक्षा करवाएगा ताकि इसे लागू करने से पहले इसकी सुरक्षा विश्वसनीयता, कुशलता एवं एकरूपता को सुनिश्चित किया जा सके।

- (2) ऐसे प्रत्येक एप्लीकेशन साफ्टवेयर में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदन को युनिक पहचान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए।

- (3) प्रत्येक अधिकृत सेवा प्रदाता संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के परामर्श से अपने एप्लीकेशन साफ्टवेयर का निर्माण करेगा जिससे उक्त अधिकृत सेवा प्रदाता इस नियमावली के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान कर सकेगा।

- (4) सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत सेवा प्रदाता निर्मित एप्लीकेशन साफ्टवेयर में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषताएं एवं क्षमताएं होनी चाहिए, अर्थात् :—

- (क) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के प्रयोग से अधिकृत एजेंटों का लॉग इन सुरक्षित रखना जो एप्लीकेशन सिस्टम में प्रवेश के लिए अपेक्षित होता है।
- (ख) अधिकृत एजेंटों का डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड भंडार में प्रवेश निश्चित करना ताकि डिजिटल हस्ताक्षर लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदनों की प्रिंटिंग करके प्रदान किया जा सके, तथा
- (ग) नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करते समय अधिकृत एजेंट द्वारा जारी किसी वाउचर या रसीद को युनिक पहचान प्रदान करना।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलिवरी का निदेशक साफ्टवेयर एप्लीकेशन को तीसरे पक्ष एजेंसी से लेखा परीक्षा करवाएगा ताकि अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा क्रियाशील बनाए जाने से पहले तथा जब भी एप्लीकेशन साफ्टवेयर में परिवर्तन किया जाता है, इसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता, निष्पादन तथा एकरूपता को सुनिश्चित जा सके।
20. अधिकृत सेवा प्रदाता या अधिकृत एजेंट द्वारा ई-सर्विस की डिलिवरी :—(1) किसी लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदन जारी करने या धन के भुगतान की रसीद हेतु किसी प्रयोक्ता के अनुरोध प्राप्त होने पर अधिकृत सेवा प्रदाता या अधिकृत एजेंट नियम 19 में विनिर्दिष्ट अपनी सुरक्षित एप्लीकेशन के जरिये किसी लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र या अनुमोदन या किसी भुगतान या प्राप्ति के लिए डाटाबेस में संबंधित विभाग के डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के भंडार में प्रवेश करेगा।
- (2) अधिकृत सेवा प्रदाता या अधिकृत एजेंट केवल अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के प्रयोग से ही प्रवेश पा सकेगा।
- (3) अधिकृत सेवा प्रदाता या अधिकृत एजेंट, विनिर्दिष्ट शुल्क, टैक्स, ड्यूटी या भुगतान को सेवा प्रभार के साथ स्वीकार करके किसी भुगतान या प्राप्ति से संबंधित लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदन या डाटाबेस रिकार्ड को डाउनलोड करेगा तथा डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के भंडारण से लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति या अनुमोदन या संबंधित डाटाबेस से भुगतान वाउचर या रसीद की छपाई करेगा तथा निर्धारित एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा निर्धारित स्टेशनरी का प्रयोग करके दस्तावेज छापेगा।
21. डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों की पुष्टि:— (1) सक्षम प्राधिकारी किसी लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, संस्वीकृति, अनुमोदन या किसी अधिकृत सेवा प्रदाता या अधिकृत एजेंट या राज्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड भंडारक द्वारा प्रदान की गई रसीद की आनलाइन पुष्टि की एक प्रणाली (पोर्टल/वेबसाइट) तैयार करवाएगा।
- (2) कोई व्यक्ति या अधिकरण जो किसी दस्तावेज या इस नियमावली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र की वैधानिकता की पुष्टि करना चाहता है, वह पुष्टि किये जाने वाले दस्तावेज पर छपे युनिक पहचान से पोर्टल या वेबसाइट में देख सकता है।

22. सूचना प्रणाली तथा अधिकृत सेवा प्रदाता तथा अधिकृत एजेंटों की लेखा परीक्षा:— (1) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदाता निदेशक अधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा राज्य में उनके अधिकृत एजेंटों के रिकार्ड तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा यथावश्यक अवधि के अन्तराल पर सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संस्थान की सूची वाली किसी एजेंसी से करवाएगा।
- (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित लेखा परीक्षा के अन्तर्गत सुरक्षा, गोपनीयता तथा सूचना की गोपनीयता, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान प्रक्रिया में प्रयुक्त किसी एप्लीकेशन साफ्टवेयर की प्रकार्यता एवं कुशलता तथा किसी अधिकृत सेवा प्रदाता या उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा रखे गए लेखाओं की सटीकता का पक्ष शामिल है।
- (3) अधिकृत सेवा प्रदाता तथा उनके अधिकृत एजेंटों के लिए आवश्यक है कि वे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदाता के निदेशक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं तथा सहायता प्रदान करें तथा लेखा परीक्षा एजेंसी के निदेशों का पालन करें तथा एजेंसी द्वारा सामने लाई गई त्रुटियों तथा कमियों को ठीक करे।
23. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान करने में विशेष स्टेशनरी का प्रयोग :—(1) अधिकृत सेवा प्रदाता तथा उसके एजेंटों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता निदेशक द्वारा निर्धारित विशेष स्टेशनरी का प्रयोग करना होगा साथ ही फार्मों, आवेदन पत्रों, लाइसेंस, परमिटों, प्रमाण पत्रों, भुगतान की प्राप्ति रसीदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदान करने के लिए सुरक्षा तत्व एक भाग के रूप में होगा।
- (2) प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों तथा परमिटों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदाता निदेशक द्वारा निर्धारित स्वरूप में एक घोषणा होगी।
24. यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार की सहमति से इन नियमों के अंतर्गत कोई अधिसूचना/आदेश जारी किया जाता है तो उक्त अधिसूचना/आदेश मान्य रहेगा तथा किसी अन्य सक्षम अधिकारी की अधिसूचना/आदेश मुख्यसचिव, दिल्ली सरकार की सहमति से जारी अधिसूचना/आदेश की प्रतिकूलता की सीमा तक अमान्य होगा।
25. अपील :— नियमावली में उल्लिखित किसी प्राधिकारी/कर्मचारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दिल्ली सरकार के अगले वरिष्ठ प्राधिकारी के पास आदेश जारी होने के तीस दिनों के भीतर की जा सकेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

अजय चगती, अतिरिक्त सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

Delhi, the 14th December, 2012

F. No. F6(168)/IT/Tech./2012/6034.—In exercise of the powers conferred under Section 90 read with Sections 6 and 6A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and Commencement.**— (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
(3) These rules shall be applicable to the National Capital Territory of Delhi
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Information Technology Act, 2000;
 - (b) “authorised agent” means an agent of the Authorised Service Provider and includes an operator of an electronically enabled kiosk or from office who is permitted to deliver public services to the users with the help of a computer resource or any communication device, by following the procedure specified under these rules;
 - (c) “Authorised Service Provider” means an agency including a body corporate or an Agency of the Government, authorised by the Director of Electronic Service Delivery, to establish and manage a system of delivering services electronically, in accordance with these rules;
 - (d) “body corporate” means any company and includes a firm, sole proprietorship or other association of individuals engaged in commercial or professional activities;
 - (e) “certificate” means a certificate required to be issued by an authority empowered under the respective Act, rule, regulation or order of the Government to issue a certificate to confirm the status, right or responsibility of a person, either natural or artificial, in accordance with any such Act, rule, regulation or order of the Government and includes a certificate in electronic form printed and delivered by Competent Authority or an Authorised Service Provider, with electronic signature on such stationery as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery;
 - (f) “Competent Authority” means the Secretaries to the Government, the Head of every Department of the Government and the Head of Government Organisations and Government Bodies, as notified by the Government from time to time;

4624 DG/12-6

- (g) **"Director of Electronic Service Delivery"** means the official of the Government notified as the Director of Electronic Service Delivery;
- (h) **"e-service"**, means a service as may be specified by notification and delivered electronically to the user;
- (i) **"electronic service delivery"** means the delivery of public services in the form of receipt of forms and applications, delivery of any license, permit, certificate, sanction or approval and the receipt or payment of money by electronic means or any other such public service rendered by following the procedure specified under these rules;
- (j) **"Government"** means the Government of National Capital Territory of Delhi;
- (k) **"notification"** means a notification published in the official Gazette;
- (l) **"official Gazette"** means the official Gazette of the Government of National Capital Territory of Delhi;
- (m) **"public service"** means service provided by the Government either through its Competent Authorities or any of its agencies either directly or through any authorized service provider, which shall include, *inter alia*, the receipt or forms and applications, delivery of any license, permit, certificate, sanction or approval and the receipt or payment of money;
- (n) **"service charge"** means the amount as may be specified by the Government to be payable to the Authorised Service Provider for electronic delivery of services rendered and does not include any duly authorized taxes, charges, dues or any other moneys due in respect of a service payable by any person to the Competent Authority concerned that are otherwise payable under the respective Act, rule, regulation or order of the Government when making an application to the concerned Competent Authority;
- (o) **"signing authority"** means an authority empowered under the respective Act, rules, regulations or order of the government to issue any license, permit certificate, sanction or approval;
- (p) **"specified"** means specified by notification in the official Gazette by the Government;
- (q) **"State Electronic Records Repository"** means an electronic repository of all electronically signed records with digital signature, maintained by Competent Authorities, for the purpose of accessing such records and delivering them to the citizens.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. **System of Electronic Service Delivery.**- (1) For the purpose of efficient delivery, the Government may authorise an Authorised Service Provider to deliver public services through electronically enabled kiosks or any other mechanism for electronic service delivery.

Explanation. – It is hereby clarified that the present rules provide for the administration of e-service delivery through Authorised Service Providers and authorised agents whereas other mechanisms of e-service delivery such as State Online Portal, Government departmental outlets and online services provided to the users directly on the web shall be administered in the normal manner by the respective Government departments and agencies.

- (2) The form of application and the format of certificate issued under these rules in relation to any e-service shall be such as may be specified by the Government.

4. **Duty of the Competent Authority to notify the list of public services to be delivered through electronic mode.**- (1) Every Competent Authority shall notify within a period of thirty days from the coming into force of these rules,-

- (a) the public services of the department, agency or body which can be delivered through electronic mode;
- (b) the date by which each such service shall be made available through electronic mode,
- (c) lay down norms for efficiency, quality and accuracy in the form of service levels;
- and
- (d) the designated officers for delivery of each such service through electronic mode.

- (2) The Competent Authority shall thereafter, review and update these publications every year or as frequently as required.

5. **Notification of signing authorities.**- (1) The Competent Authorities shall notify the list of signing authorities in respect of different public services and local limits of their respective jurisdictions in the State duly specifying the nature of such service, the names of the signing authorities, the duration of the authority and the extent of jurisdiction of each such authority.

- (2) The Competent Authorities shall inform the Director of Electronic service Delivery immediately with respect to retirements, transfers, suspensions or termination from services of employees holding positions of signing authorities.

- (3) The signing authorities shall also inform their Competent Authorities immediately with respect to their retirements transfers, suspensions and terminations and

Competent Authorities shall get the changes mentioned in clause (2) implemented in their respective application software.

6. Functions and Powers of Director of Electronic Service Delivery.- (1) The Director of Electronic Service Delivery shall discharge the following functions and powers, namely:-

- (a) to authorise, suspend or terminate the services of the Authorized Service Providers;
- (b) to determine norms relating to the selection of authorised agents by the Authorised Service Providers and authorised agents;
- (c) to determine functions, responsibilities and liabilities of Authorised Service Providers and authorised agents;
- (d) to determine norms on the service levels to be complied with by the Authorised Service Providers and authorised agents;
- (e) to determine service charges to be charged by the Authorised Service Providers and authorised agents for providing e-services;
- (f) to determine terms and conditions relating to the authorisation, suspension or termination of the services of the Authorised Service Providers and authorised agents;
- and
- (g) to make alternative arrangements for delivery of e-services, in case of such suspension or termination of services of Authorised Service Providers and authorised agents.

(2) Director of Electronics Service Delivery may delegate any of his power to any official of Government of NCT of Delhi or Autonomous Body/Local Body of Government of NCT of Delhi through an administrative order.

7. Authorised Service Providers for Electronic Service Delivery.- The Authorised Service Provider shall provide the notified public services electronically to the users in conformity with these rules, by establishing appropriate delivery infrastructure and a network or authorised agents, as determined by the Director of Electronic Service Delivery.

8. Appointment of authorised agents by the Authorised Service Provider.- (1) The Authorised Service Provider may appoint such number of Authorised Agents, as may be required to delivery the services electronically to fulfil the norms of efficiency, quality and accuracy laid down by the Competent Authority.

(2) The Authorised Service Provider shall ensure that he as well as all the authorised agents obtain Digital Signature Certificates before they commence operations for delivery of public service electronically.

(3) The Authorised Service Provider may also impart appropriate training to the authorised agent to impart them the skills required to deliver the electronic services efficiently and in an error-free manner.

9. **Commencement of operations by Authorised Service Provider.**- The Authorised Service Provider shall commence its commercial operation for Electronic Service Delivery only after -

(a) he has confirmed in writing or through e-mail duly signed by digital signature to the Director of Electronic Service Delivery with respect to the adoption of procedures and standards specified under these rules; and

(b) he has installed facilities and infrastructure needed for efficient delivery of electronic services and in an error-free manner in terms of norms laid down by the Director of Electronic Service Delivery and confirm the same in writing or through e-mail duly signed by digital signature to the Director of Electronic Service Delivery.

10. **Authorised Service Provider to collect service charge.**- (1) The application for an e-service submitted by a user to an Authorised Service Provider or an authorised agent shall be accompanied by such service charge as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery which is payable in cash to the Authorised Service Provider, at the time of making the application.

(2) The Director of Electronic Service Delivery may determine service charges by notification for e-services.

(3) The service charges may be different for different e-services such as, -

(a) the status enquiry;

(b) print-outs related to e-services;

(c) the scanning of documents related to e-services;

(d) The acknowledgement receipt;

and

(e) Any other e-service.

(4) The service charge shall not include any duly authorized taxes, charges, dues or any other moneys due in respect of a service payable by any person to the Competent Authority concerned that are otherwise payable under the respective Act, rule,

4624 DG/12-7

regulation or order of the Government when making an application to the concerned Competent Authority.

11. **Fee to be collected by service provider.-** (1) Any fee or duly authorized taxes, charges, dues or any other money due in respect of a service payable by any person to the Competent Authority concerned that are otherwise payable under the respective Act, rule, regulation or order of the government when making an application to the concerned Competent Authority, shall also be collected by the Authorised Service Provider or the authorized agent as the case may be, except for those payments that are ordinarily required to be made in the form of court fee stamps or treasury challans.
- (2) The fee collected by the Authorised Service Provider or the authorised agent shall be remitted with the Government treasury as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery by the Authorised Service Provider or the authorised agent as the case may be, in its entirety.
12. **Remittance or service charge and fee by the service provider.-** (1) Out of the service charge collected by the Authorised Service Provider or the authorised agent for an e-service, a percentage of the service charge as may be determined from time to time by the Director of Electronics Delivery may be apportioned to the Government.
- (2) The share of the Government out of the service charge so collected shall be remitted by the Authorised Service Provider or the authorised agent to Government treasury as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery.
13. **Presumption with regard to service charge paid to service provide and other conditions of obtaining e-services.-** (1) Where any person pays a service charge to an Authorised Service Provider or an authorised agent in respect of any notified e-service, the print-out or the electronic prompt acknowledging the payment in the relevant form and manner as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery and provided to such person by the Authorised Service Provider or authorised agent shall normally be taken as proof of such payment and it shall be presumed that in normal circumstances the dues or claims, for which the acknowledgement is purportedly issued, have been satisfied to that extent.
- (2) The payment of service charges to the Authorised Service Provider or the authorised agent shall by no means create any right or title, temporary or permanent in nature in favour of a person concerned regarding obtaining the notified e-services.
- (3) Mere payment does not necessarily ensure the delivery of services, if all conditions associated with delivery of the service are not met fully at the time of making payment to the Authorised Service Provider or the authorised agent.
14. **Receipt or payment of money by or in favour of Government adopting the system of Electronic Service Delivery.-** The receipt or payment of money by or in favour of Government adopting the system of Electronic Service Delivery shall be deemed to be a receipt or payment effected in compliance with the Financial Code and Treasury Code of the Government.

- 15. Filing of form, application or any other document.-** (1) Any form, application or any other document referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Act may be filed with any office, authority, body, agency or Authorised Service Provider authorised by the Government of National Capital Territory of Delhi using the application software specified by it.
- (2) The office, authority, agency or Authorised Service Provider referred to in sub-clause (1) shall, while developing such software, take into account the following features of the electronic record, namely:-
- (a) life time;
 - (b) preservability;
 - (c) accessibility;
 - (d) readability;
 - (e) comprehensibility in respect of linked information;
 - (f) evidentiary value in terms of authenticity and integrity;
 - (g) controlled destructibility; and
 - (h) augmentability.
- 16. Issue or grant of any license, permit, sanction or approval.-** (1) Any license, permit, sanction or approval referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 6 of the Act may be issued or granted by using the application software specified under rule 15.
- (2) The license, permit, certificate, sanction or approval so issued shall be in the form prescribed in the respective Act, rule, regulation or order and shall contain the name and designation of the signing authority who had digitally signed and approved the electronic record along with the date and time of creation of such record.
- 17. Creation or repository of digitally signed electronic records.-** (1) The Competent Authority may, as soon as, after the coming into effect of these rules create, establish and maintain a repository and database of digitally signed electronic records together with the associated application software and workflow to enable Authorised Service Provider or the authorised agents to access such licenses, permits, certificates, sanctions or approvals, as the case may be, and deliver them to the user.
- (2) The relevant security procedures, as specified by the Government, shall be followed by such Competent Authorities, in respect of the electronic data, information, applications, repository of digitally signed electronic records and information technology assets under their respective control.
- 18. Procedure for making changes in a repository of digitally signed electronic records.-** (1) Any Competent Authority or any signing authority, either *suo motu*, or on an application by an interested party, may make or order to make an appropriate change in a repository of digitally signed electronic records, after following the procedure prescribed in the respective Act, rule, regulation or order.
- (2) Any such authority shall have privileges for making or ordering changes only in respect of the electronic records pertaining to its own jurisdiction.

4624 DG/12-8

(3) Any change effected to any record in a repository of digitally signed electronic records, and any addition or deletion of a record from such repository of electronic records shall invariably be digitally signed by the respective authority and an electronic audit trail of all such changes shall be maintained.

19. Creation of secure application software for Electronic Service Delivery.- (1) The Competent Authority shall get appropriate application software created, using which, the Signing Authorities, shall digitally sign the license, permit, certificate, sanction or approvals, and get the same audited by a third party agency, so as to ensure its security, reliability, performance and consistency, before it is deployed.

(2) Every such application software shall, *inter alia*, possess the capability to assign a unique identification to each license, permit, certificate, sanction or approval.

(3) Every Authorised Service Provider shall create its own application software in consultation with the respective Competent Authorities, which shall enable such Authorised Service Providers to deliver electronic services in accordance with these rules.

(4) Every such application software created either by the Competent Authority or the Authorised Service Provider shall, *inter alia*, possess the following features and capabilities, namely:-

- (a) secure Login of Authorised Agents, as are required to access the application system, through use of Digital Signature Certificates;
- (b) secure access of Authorised Agents, to the repositories of digitally signed electronic records maintained by the Competent Authorities, for printing and delivery of the digitally signed license, permit, certificate, sanction or approvals; and
- (c) assign a unique identification to the voucher or receipt issued by any authorised agent while providing electronic services to the citizens.

(5) The Director of Electronic Service Delivery shall get such application software audited by a third party agency, as to ensure its security, reliability, performance and consistency, before it is deployed by the Authorised Service Provider and also as and when changes are made in the application software.

20. Delivery of e-Services by the Authorised Service Provider or Authorised Agent.- (1) On a request made by a user for provision of a service, relating to the issue of any license, permit, certificate, sanction or approval and to the receipt or payment of money, the Authorised Service Provider or the authorised agent shall access the respective departmental repository of digitally signed electronic records through their secured application specified in rule 19, in respect of any license, permit, certificate or approval or the database in respect of any payment or receipt.

(2) The Authorised Service Provider or the authorised agent shall be permitted to have such access only with the use of its digital signature certificate.

(3) The Authorised Service Provider or the authorised agent shall accept the specified fees, tax, duty or payment along with the service charge download the related license, permit, certificate, sanction or approval or the database record relating to any payment or receipt, print the license, permit, certificate, sanction or approval from the repository of digitally signed electronic records, or the payment voucher or receipt from the relevant database, and print the document using the secure application software and the secure stationery.

21. Verification of Digitally Signed documents.- (1) The Competent Authorities shall cause to be created a system (portal/website) of online verification of any license, permit, certificate, sanction, approval or receipt delivered by any Authorised Service Provider or the authorised agent or the State Electronic Records Repository.

(2) Any person or authority, desirous of verifying the authenticity of any document or certificate issued under these rules, may access such portal or the website using the unique identification printed on the document sought to be verified.

22. Audit of the Information Systems and Accounts of Authorised Service Provider and authorised agents.- (1) The Director of Electronic Service Delivery shall cause an audit to be conducted of the records and accounts of the Authorised Service Providers and their authorised agents in the State at such intervals as deemed necessary by an agency empanelled as an information security auditing organization.

(2) The audit referred to in sub-rule (1) may cover aspects such as security, confidentiality and privacy of information, the functionality and performance of any application software used in the electronic delivery of services and the accuracy of accounts kept by the Authorised Service Providers and their authorised agents.

(3) It shall be incumbent on the Authorised Service Provider and their authorised agents to provide such information and assistance to the audit agencies appointed by the Director of Electronic Service Delivery to comply with the directions given by the audit agencies and to rectify the defects and deficiencies pointed out by the audit agencies.

23. Use of special stationery in Electronic Service Delivery.- (1) The special stationery used by the Authorised Service Providers and its agents for delivery of the services shall be determined by the Director of Electronic Service Delivery with accompanying security features for forms, applications, license, permits, certificates, receipts of payment and such other documents as part of the Electronic Service Delivery.

(2) The certificates, licenses and permits shall carry a declaration in the format as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery.

24. If any notification/order is issued with the concurrence of Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi as Competent Authority under these rules, then the said notification/order will prevail and any other notification/order of any Competent Authority shall be void to the extent of repugnancy vis-à-vis the notification/order issued

with the concurrence of the Chief Secretary , Government of National Capital Territory of Delhi.

- 25. Appeal .-** An appeal against the order of any authority/official mentioned in the rules may be preferred before the next higher authority of Government of National Capital Territory of Delhi with in thirty days of the issuance of order.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

AJAY CHAGTI, Addl. Secy. (IT)